भोपाल | गुरुवार | 04 सितंबर 2025 | वर्ष 69 | अंक 211 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com | twitter.com/Nava_Bharat | fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से
भोपाल 70 वां वर्ष संस्करण

4 भारतीयों पर दुनियाभर में नस्लवादी हमले

5 पुतिन-शाहबाज पर ट्रम्प ने कसा तंज

8 भांबरी ने किया कमाल, जूनियर बाहर

9 इस सीजन पूरा कपास खरीदा जाएगा : सरकार

भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था

जर्मनी ने ईयू-भारत मुक्त व्यापार समझौते का किया समर्थन

नयी दिल्ली, 3 सितंबर (वार्ता). जर्मनी ने बुधवार को कहा कि वह भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का प्रबल समर्थक है और उसे इस समझौते के इस साल के अंत तक हो जाने की उम्मीद है. विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के बीच नयी दिल्ली में हुई विस्तृत वार्ता के बाद दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, नवाचार और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को गहराई देने पर सहमति जताई. साथ ही जर्मनी ने आतंकवाद को लेकर भारत के रुख का भी समर्थन किया है और कहा है कि वह आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत के साथ है.

संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा, हम दुनिया को आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक अनिश्चितता की दोहरी चुनौतियों का सामना करते हुए देख रहे हैं. हमारा मानना है कि रणनीतिक स्वायत्तता वाला एक बहुध्रुवीय विश्व, प्रमुख देशों के बीच गहन परामर्श और सहयोग के

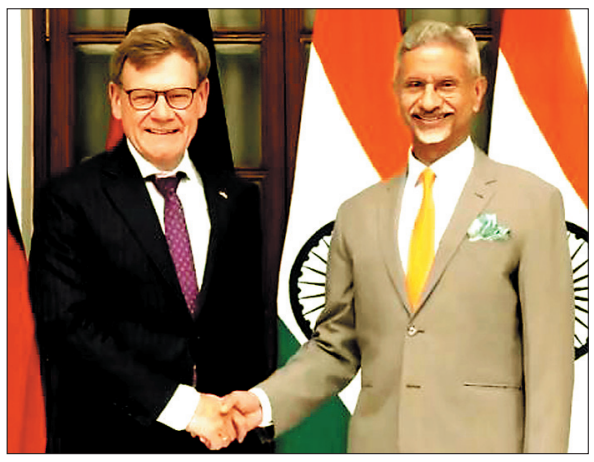

माध्यम से ही सर्वोत्तम व्यवस्था बना सकता है. उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री के खुले और रचनात्मक दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि भारत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार है.

वहीं, वेडफुल ने कहा कि जर्मनी ईयू और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते का प्रबल समर्थक है. उन्होंने उम्मीद जतायी कि भारत-ईयू एफटीए इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा. उल्लेखनीय है कि ईयू भारत के माल और सेवाओं का एक प्रमुख बाजार है और दोनों पक्षों के बीच एफटीए के लिए वार्ता चल रही है. जर्मनी ईयू की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक है और व्यापार तथा निवेश में भारत का एक प्रमुख भागीदार है.

उन्होंने यूक्रेन-रूस युद्ध के संबंध में कहा, हमारे लिए यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले तो उन्होंने यूक्रेन में शांति के लिए शीघ्र सहमति पर जोर दिया. जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा, 'हम अपने यूरोपीय मित्रों के साथ मिल कर प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्रातिशीघ्र पुन: शांति स्थापित हो. वेडफुल ने भारत और चीन के बीच संबंधों के बारे में कहा कि जर्मनी इसे सकारात्मक दृष्टि से देखता है लेकिन हमारा यह भी मानना है कि वैश्विक व्यवस्था को उसके सही रूप में बनाये रखने के लिए हमें चीन के प्रति सावधान रहने की जरूरत है. जर्मनी चीन को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है. विदेश मंत्री डा.एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दौरान जर्मनी में लंबे समय से फोस्टर केयर में फंसी भारतीय बच्ची अरिहा शाह के मुद्दे के जल्द समाधान और उसके सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करने तथा उसे उसके मात पिता को सौंपने की मांग की है.

> केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने जर्मन विदेश मंत्री के साथ व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की बैठक की सह-अध्यक्षता की. इस दौरान बाजार तक पहुंच, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई. गोयल ने कहा, हमने डिफेंस, स्पेस, इनोवेशन और ऑटोमोबाइल में सहयोग पर भी चर्चा की, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाया जा सके. साथ ही हमारी चर्चा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी, साथ ही साझा विकास और समृद्धि के लिए इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर भी चर्चा हुई.

सेमीकॉन इंडिया में पहुंचे पीएम मोदी

- माइक्रॉन के स्टॉल में देखा मेड इन इंडिया चिप

नयी दिल्ली, 03 सितंबर (वार्ता). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अचानक द्वारका के यशोभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने सेमीकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन विभिन्न कंपनियों के स्टॉलों पर जाकर उनके उत्पाद देखे और उनके बारे में जानकारी ली.

मोदी अमेरिका की कंपनी लैम रिसर्च के स्टॉल पर गये और वहां मौजूद लोगों से बात की. इसके बाद वह माइक्रॉन के स्टॉल पर गये, जहां उन्होंने कंपनी द्वारा भारत में निर्मित टेस्ट चिप देखा. उन्होंने सूक्ष्मदर्शी लेंस से इस चिप को देखा, जिसमें बेहद छोटे अक्षरों पर 'मेड इन इंडिया' लिखा था. उन्होंने वहां भी कंपनी के विशेषज्ञों से बात की.

उल्लेखनीय है कि माइक्रॉन और टाटा दो ऐसी कंपनियां हैं, जिन्होंने देश में चिप निर्माण संयंत्र में पायलट के तौर पर टेस्ट चिप बनाने शुरू कर दिये हैं. स्वदेशी चिप के इस साल के अंत तक बाजार में आने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री ने मंगलवार को तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि पहला वाणिज्यिक स्वदेशी चिप इसी साल बाजार में आ जायेगा.

सरकार ने देश को दुनिया के सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है, जो अपनी शत-प्रतिशत जरूरत पूरी करने के बाद दुनिया को निर्यात भी कर सके. प्रधानमंत्री का बिना पूर्व नियोजित कार्यक्रम के आज सुबह लगातार दूसरे दिन यशोभूमि पहुंचना दिखाता है कि वह इस क्षेत्र को कितना महत्व देते हैं.

> मोदी बुधवार को काफी देर तक यशोभूमि में रुके और देश-विदेश की कंपनियों के स्टॉल में जाकर सेमीकंडक्टर क्षेत्र की मौजूदा स्थिति तथा भविष्य की प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी ली. सेमीकॉन इंडिया की शुरुआत 2021 में हुई थी. इसका उद्देश्य स्वदेशी और विदेशी कंपनियों को देश में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना और इस उद्योग के लिए इकोसिस्टम विकसित करना है.

एक नजर में

के कविता ने दिया एमएलसी पद से इस्तीफा

हैदराबाद /नयी दिल्ली. भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री तथा विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के कविता ने पार्टी से निलम्बित होने के एक दिन बाद बुधवार को पार्टी तथा परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. बीआरएस के सहयोगी संगठन तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के कविता ने विधान परिषद की सदस्यता से अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंप दिया.

20 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा. छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025 और नियद नेल्ला नार योजना से प्रभावित होकर बुधवार को सुकमा जिले में 20 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. इनमें नौ महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं. आत्मसमर्पण करने वालों में 11 इनामी नक्सली भी हैं, जिन पर कुल 33 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. आत्मसमर्पण की इस प्रक्रिया में जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा यूनिट की अहम भूमिका रही है.

पाक में विस्फोट में 13 लोगों की मौत, 31 घायल

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में हुए एक जोरदार धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गयी और अन्य 31 घायल हो गए. सूबे के स्वास्थ्य मंत्रालय प्रवक्ता वसीम बेग ने हताहतों की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है. ये विस्फोट सूबे की राजधानी क्वेटा के शाहवानी स्टेडियम इलाके में एक राजनीतिक सम्मेलन के पास हुआ.

गुस्ताखी माफ

ईडी ने डीएमएफ फंड घोटाले में की 18 ठिकानों पर छापेमारी

रायपुर. छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने जिला खनिज न्यास फंड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और उसके दुरुपयोग के मामले में बुधवार को प्रदेश के विभिन्न शहरों में व्यापक छापेमारी शुरू की. ईडी की यह कार्रवाई उन व्यापारियों, ठेकेदारों और बिचौलियों के ठिकानों पर केंद्रित है, डीएमएफ फंड को बीज निगम, छत्तीसगढ़ के जरिए अवैध रूप से बड़े पैमाने पर गबन करने का आरोप है. ईडी की टीमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में करीब 18 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई कर रही हैं. रायपुर के शंकर नगर स्थित कारोबारी विनय गर्ग के आवास पर भी ईडी की टीम तलाशी ले रही है.

गृहमंत्री शाह के आवास पर बैठक

भाजपा नेताओं ने किया बिहार चुनाव की रणनीति पर मंथन

नयी दिल्ली, 03 सितबंर (वार्ता). भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति एवं तैयारी को लेकर बुधवार को व्यापक चर्चा की.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इस संबंध में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में शाह के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार में पार्टी के प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सांसद संजय जायसवाल, बिहार के सह प्रभारी दीपक प्रकाश तथा कुछ अन्य नेता मौजूद थे.

> बैठक में हुए विचार-विमर्श के बारे में अधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई लेकिन सूत्रों के अनुसार इस अहम बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के अन्य दलों के साथ सीटों के आवंटन तथा पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार किया गया.

पंजाब आपदा प्रभावित राज्य घोषित, 7 तक अवकाश

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का करेंगे दौरा

चंडीगढ़, 03 सितंबर (वार्ता). हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश से भाखड़ा और पौंग बांध के जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है. लगातार बारिश और बाढ़ को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे.

ये जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की. उन्होंने बुधवार सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पंजाब और कृषि मंत्री से फोन पर हालात पर चर्चा की.

प्रदेश के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 1200 से अधिक गांव प्रभावित हुये हैं. बाढ़ ने अब तक 30 लोगों की जान ले ली है और 3.54 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुये हैं. घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है. मोहाली में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है.

बाढ़ की चपेट में 1200 से अधिक गांव

राज्य सरकार ने पूरे पंजाब को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है. मुख्य सचिव के ए पी सिन्हा के पत्र के अनुसार सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी हैं. स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां भी सात सितंबर तक बढ़ा दी गयी हैं.

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पंजाब भर के सभी सरकारी/सहायता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक सात सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे.

> सिन्हा ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है. पत्र में बताया गया है कि लगातार बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 1200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं और लाखों लोग प्रभावित हुये हैं. उन्होंने अधिकारियों और विभागों को पत्र में छह निर्देश भी दिये हैं. जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि अगर किसी इलाके में बाढ़ या आपदा का खतरा गंभीर हो जाये, तो वे कानून के तहत सभी जरूरी आदेश जारी कर सकते हैं.

सीएए पर कटऑफ डेट बढ़ाकर 2024 की गई

- केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

नयी दिल्ली, 03 सितम्बर. केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए अल्पसंख्यकों के लिए कटऑफ तारीख बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2024 कर दी है.

आदेश के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के वे लोग, जो 31 दिसम्बर 2024 तक भारत आए हैं, उन्हें पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज के बिना भी देश में रहने की अनुमति दी जाएगी. यह आदेश आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत जारी हुआ है.

उल्लेखनीय है कि सीएए के तहत पहले 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आए शरणार्थियों को ही नागरिकता का प्रावधान था. नए आदेश से विशेषकर पाकिस्तान से आए उन हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो 2014 के बाद भारत आए और अब तक अनिश्चितता में जी रहे थे. उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी.

बाढ़ प्रभावित : राज्यों को सहायता राशि दे सरकार

- जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में बारिश से तबाही
- राहुल गांधी ने बारिश से हुई तबाही पर चिंता जताई

नयी दिल्ली, 03 सितंबर (वार्ता). कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करने की मांग की है.

गांधी ने कहा कि इन राज्यों की स्थिति आपदाओं के कारण अत्यंत

वीभत्स हो गई है और वहां जन जीवन संकट में आ गया है इसलिए सरकार को प्रभावित राज्यों के लिए और विशेषकर किसानों के हित में विशेष राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर बुधवार को एक पोस्ट में प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा मोदी जी, पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है.

> जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है. ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत आवश्यक है. हज़ारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने कहा मैं आग्रह करता हूं कि इन राज्यों के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की तत्काल घोषणा की जाए और राहत एवं बचाव कार्यों को तेज़ किया जाए.

महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 1,500 करोड़ की योजना मंजूर

नयी दिल्ली, 03 सितंबर (वार्ता). केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की योजना को बुधवार को मंजूरी दी जिसमें प्रति इकाई अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत और परिचालन सब्सिडी दी जायेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना के तहत पूरी बैटरी के अपशिष्ट और ई-कचरे के पुनर्चक्रण की क्षमता विकसित की जायेगी ताकि ऐसी पुरानी और बेकार हो चुकी चीजों से महत्वपूर्ण खनिज तत्व निकालकर उनकी उपलब्धता बढ़ायी जा सके. यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू क्षमता

और आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती लाना है. सरकार का मानना है कि निकट भविष्य में आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक विवेकपूर्ण तरीका द्वितीयक स्रोतों का पुनर्चक्रण है. इस योजना के अंतर्गत मान्य पुनर्चक्रण की सामग्री में ई-कचरा, लिथियम आयन बैटरी (एलआईबी) स्क्रैप, और ई-कचरा के अलावा वैध जीवन-काल पार कर चुके वाहनों के कैटेलिटिक कनवर्टर आदि शामिल हैं. विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए बड़े स्थापित पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ-साथ स्टार्ट-अप इकाइयों सहित छोटे और नये पुनर्चक्रणकर्ता भी आवेदन कर सकते हैं. इस योजना की एक-तिहाई राशि ऐसे नये और छोटे उद्यमों के लिए निर्धारित की गयी है.

वन-टू-वन चर्चा | नई दिल्ली में हुआ इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी इन पीएम-मित्रा पार्क

इंटरैक्टिव सेशन में मिले 12 हजार 508 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

- पूंजी निवेश के लिए देश का मॉडल स्टेट बना मप्र

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 3 सितंबर. नई दिल्ली के होटल आईटीसी मौर्या में बुधवार को मप्र के धार स्थित पीएम-मित्रा पार्क में इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज के इंटरैक्टिव सेशन हुआ. सेशन में निवेशकों ने मप्र में 12 हजार 508 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया.

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हम सब बदलते दौर के साथी हैं. उम्मीदों और अवसरों का विराट क्षितिज

हमारे सामने है. अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए निवेश का एक स्वर्णिम अवसर आप सबके सामने है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों से आग्रह किया कि वे बेहिचक मध्यप्रदेश में पूंजी लगाएं. निवेश आपका, बिजनेस आपका, प्रॉफिट भी आपका और सरकार की सभी सुविधाएं भी आपके लिए ही हैं. उन्होंने निवेशकों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप सभी अपने कारोबार में आगे बढ़ें, आपके व्यापार-व्यवसाय की सफलता की गारंटी हमारी सरकार है.

मध्यप्रदेश पूंजी निवेश के लिए देश का मॉडल स्टेट बन रहा है. शीघ्र ही धार के पीएम-मित्रा पार्क का भूमि-पूजन होगा. यह पार्क भारत को विश्व की टेक्सटाइल केपिटल बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है. हम मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान अंतर्गत मेक इन इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे. सेशन में देश के टेक्सटाइल सेक्टर के बिजनेस टायकून्स, कॉमर्शियल हाउसेस और इन्वेस्टर्स शामिल हुए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार जिले के बदनावर के समीप स्थापित होने वाले पीएम-मित्रा पार्क में निवेश की अपार संभावनाओं पर कपड़ा उद्योग से जुड़े विभिन्न उद्योगपतियों से विचार-विमर्श भी किया.

> **धार परियोजना दशकों पुरानी मांग का समाधान : केंद्रीय मंत्री**
>
> केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि धार का पीएम-मित्रा पार्क केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि वस्त्र उद्योग की दशकों पुरानी मांग का समाधान है. यह पार्क भारत को वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में एक नई पहचान देगा और देश का सबसे बड़ा एकीकृत टेक्सटाइल हब बनेगा. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के सामने लगभग 800 बिलियन डॉलर का वैश्विक टेक्सटाइल बाजार अवसर के रूप में मौजूद है और केन्द्र सरकार इसे हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है. इंटरैक्टिव सेशन में टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा की गई.

छोटी - बड़ी इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि तय

लाभार्थियों की अधिक संख्या सुनिश्चित करने के लिए प्रति इकाई कुल प्रोत्साहन (पूंजीगत व्यय और ओपेक्स सब्सिडी) बड़ी इकाइयों के लिए 50 करोड़ रुपये और छोटी इकाइयों के लिए 25 करोड़ रुपये तय की गयी है. इसके अंतर्गत ओपेक्स सब्सिडी की सीमा क्रमश: 10 करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये होगी. सरकार को इस योजना से कम से कम 2,70,000 टन वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता विकसित होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 40,000 टन वार्षिक महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन होगा. इससे लगभग 8,000 करोड़ रुपये का निवेश आने और 70,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है.